2024-25

बजट सवेरा टाइम्स

अंधेरे से उजाले की ओर...

II

REGISTRATION NO. PB-JL-058/20-22 | DAINIK SAVERA TIMES, CHANDIGARH | चंडीगढ़, बुधवार, 24 जुलाई 2024 | WWW.DAINIKSAVERATIMES.COM | ■ पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा से प्रकाशित

मुख्य ऐलान

इन्फ्रास्ट्रक्चर

अमृतसर-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। पीएम ग्राम सड़क योजना का फेज-4 शुरू होगा। जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बसावटों में सड़कें बनाई जाएंगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे।

उद्योग

मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफार्म में शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई। एमएसएमई सैक्टर में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सके, इसके लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे।

नौकरियां

रोजगार के लिए कई योजनाएं शुरू। पहली नौकरी पर 1 लाख रुपए से कम की सैलरी पर 15,000 रुपए की मदद सरकार करेगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ के अंशदान में हर महीने 3,000 रुपए देगी।

अपना घर

पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई। पीएम आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को घर मिलेंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किफायती दरों पर लोन मिल सके, इसके लिए ब्याज सबसिडी भी शुरू होगी।

शिक्षा

देशभर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लोन पर 3 प्रतिशत का ब्याज सरकार देगी। इसके लिए ई-वाऊचर्स आएंगे, जो हर साल एक लाख छात्रों को मिलेंगे।

महिलाएं

महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आबंटित। वर्किंग वुमैन हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल और क्रैच की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएंगी।

इलैक्ट्रॉनिक्स

मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर को लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया। कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा।

कॉर्पोरेट

ई-कॉमर्स आप्रेटरों पर टीडीएस की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया। विदेशी कंपनियों पर कार्पोरेट टैक्स की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई।

किसान

2 साल में 1 करोड़ किसानों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी। फसलों का डिजीटल सर्वे होगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। कृषि और उससे जुड़े सैक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगे।

युवा

टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए हर महीने का भत्ता और 6,000 रुपए एकमुश्त सहायता की जाएगी।

कार-बाइक

कोबाल्ट, लिथियम जैसे खनिजों पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। लिथियम बैटरी से चलाने वाले वाहन दो पहिया और चार पहिया के दाम घटने की उम्मीद है।

सेहत

कैंसर की 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया। इससे दवाएं सस्ती होंगी। एक्स-रे मशीनों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटैक्टरों पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई।

पर्यटन

गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को विश्वस्तीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए सहायता की जाएगी।

सेना

रक्षा पर 2024-25 में कुल 6,21,940 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 1.72 लाख करोड़ रुपए हथियारों की खरीद पर खर्च होंगे। जबकि 1.41 लाख करोड़ का खर्च पैंशन पर होगा।

बिहार-आंध्र

बिहार में पटना-पूर्णिया एक्सप्रैस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रैस-वे का विकास होगी। वहीं, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला नया पुल बनेगा। नए एयरपोर्ट, मैडीकल और स्पोर्टस प्रोजैक्ट्स भी शुरू होंगे। वहीं, आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ रुपए का स्पैशल पैकेज मिलेगा।

सरकारी पैंशनर्स को 25,000 रुपए तक की मिलेगी छूट!

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए फैमिली पैंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैमिली पैंशन पर छूट 15,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका मतलब है कि पैंशन पर होने वाली कमाई पर फैमिली पैंशन का लाभ लेने वाले सरकारी पैंशनर्स 25,000 रुपए तक के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। जो पैंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।

सोना, चांदी, इंपॉर्टेड मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती

सवेरा न्यूज/एजैंसी

नई दिल्ली, 23 जुलाई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जिसमें सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद सोना, चांदी तथा अन्य कीमती धातुओं के साथ-साथ आयातित मोबाइल फोन, कुछ कैंसर की दवाएं और चिकित्सकीय उपकरण भी सस्ते होने की उम्मीद है। हालांकि, आयातित बड़ी छतरियां तथा प्रयोगशाला रसायन जैसी कुछ वस्तुएं भी मूल सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण महंगी हो जाएंगी।

सस्ती-महंगी वस्तुएं

सस्ता...

सोने की छड़ें व 'डोर', चांदी की छड़ें व 'डोर', प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम और इरिडियम कीमती धातुओं के सिक्के, आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण के निर्माण में उपयोग के लिए सभी प्रकार के पॉलीइथिलीन, चिकित्सकीय, शल्य चिकित्सकीय, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए फ्लैट पैनल डिटैक्टर (सिंटिलेटर सहित), आयातित सैल्युलर मोबाइल फोन, चार्जर/एडाप्टर, सैल्युलर मोबाइल फोन की प्रिंटेड सर्कट बोर्ड असैंबली (पीसीबीए), सौर सैल या सौर मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट पूंजीगत सामान, ऐसे पूंजीगत सामान के विनिर्माण के कलपुर्जे, शिया नट, महत्वपूर्ण खनिज, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड, पोटैशियम के नाइट्रेट, इस्पात क्षेत्र में फेरो निकेल तथा ब्लिस्टर कॉपर, कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र में 'स्पैन्डेक्स यार्न' के निर्माण में उपयोग होने वालो मेथिलीन डाइफेनिल डाइ-आइसोसाइनेट (एमडीआई)।

कार्टूनिस्ट **विश्वामित्र**

महंगा....

पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लैक्स फिल्में (जिन्हें पीवीसी फ्लैक्स बैनर या पीवीसी फ्लैक्स शीट भी कहा जाता है), बड़ी छतरियां, प्रयोगशाला रसायन, सौर सैल या सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए सौर ग्लास सौर सेल या सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए टिनयुक्त तांबा इंटरकनैक्ट।

1 दिन में 3400 रुपए तोला तक टूटी सोने की कीमतें

सवेरा न्यूज/प्रतीक

आनंद सीकरी।

मनोज ढांडा।

लुधियाना, 23 जुलाईः भारत सरकार ने आम बजट में सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 से घटाकर 6 फीसदी कर दी। मंगलवार को बाजार बंद होने तक सोने की कीमत 3400 रुपए तोला (प्रति 10 ग्राम) व चांदी की कीमत 4 हजार रुपए किलो तक टूट गई। मंगलवार को सोने (24 कैरेट) की कीमत 75200 रुपए पर खुली थी, किन्तु इंपोर्ट ड्यूटी घटने की घोषणा होने के बाद बाजार बंद होने तक कीमत 71800 रुपए तोला तक आ गई। चांदी की कीमत 92000 रुपए किलो से कम होकर 88000 रुपए किलो तक आ गई। लुधियाना ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रधान आनंद सीकरी ने बताया कि देश भर के ज्वैलर्स लंबे समय से सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग कर रहे थे। इंपोर्ट ड्यूटी 15 से 6 फीसदी किया जाना एक बेहद सराहनीय फैसला है। इससे सोने चांदी की समगलिंग पर काफी हद तक रोक लगेगी। महासचिव मनोज ढांडा का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से सोने-चांदी की कीमतों पर काफी हद तक लगाम लगेगी। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के चलते ग्राहक ने बाजार से दूरी बना ली थी। उम्मीद है कि इस फैसले से सोने एवं चांदी के आभूषण व्यवसाय को बल मिलेगा।

पीटीआई ग्राफिक

बजट अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करेगा

आम बजट दूरदर्शी, जनहितैषी और विकासोन्मुखी है। यह रोजगार तथा अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करके देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की राह पर ले जाएगा। बजट भारत की उद्यमशीलता को बढ़ाने और व्यापार करने में सुगमता के साथ आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'दृढ़ प्रतिबद्धता' को दर्शाता है।

–अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

सरकार की रोजगार को बढ़ावा देने को ईपीएफओ के जरिए 3 योजनाओं की घोषणा

पहली बार ईपीएफओ की योजनाओं से जुड़ने वालों को एक महीने का वेतन देगी सरकार

3 किस्तों में दिया जाएगा एक महीने का वेतन, जो अधिकतम 15,000 रुपए तक होगा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए कामगारों के लिए ईपीएफओ के जरिए 3 योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं के लिए कुल केंद्रीय परिव्यय 1.07 लाख करोड़ रुपए है। निर्मला सीतारण ने बजट भाषण में कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार इससे जुड़ने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देंगी। इनसे कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन मिलेगा। उन्होंने सदन को बताया कि सभी संगठित क्षेत्रों में पहली बार ईपीएफओ की योजनाओं से जुड़ने वालों को योजना-क के तहत एक महीने का वेतन सरकार देगी। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन दिया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपए तक होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता सीमा एक लाख रुपए प्रति माह वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। तीनों योजनाओं के लिए कुल केंद्रीय परिव्यय 1.07 लाख करोड़ रुपए (योजना-क के लिए 23,000 करोड़ रुपए, योजना-ख के लिए 52,000 करोड़ रुपए और योजना-ग के लिए 32,000 करोड़ रुपए) होगा।

योजना-ख

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए लाई गई योजना-ख पहली बार ईपीएफओ से जुड़ने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के पहले 4 सालों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को उनके ईपीएफओ अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना-ग

नियोक्ताओं की सहायता कर सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना-ग लाई गई है। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

केंद्र से विशेष मदद मिलनी शुरू

केंद्र सरकार से विशेष मदद मिलनी शुरू हो गई है। अब राज्य का और तेजी से विकास होगा। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर हम लोग पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। पहले ही हम लोग कह दिए थे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है तो विशेष मदद की जाए।

–नीतीश कुमार, सीएम बिहार

कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर

बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार और कौशल बढ़ाने और मानव संसाधन और सामाजिक न्याय को ऊपर उठाने का वादा किया गया है। बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और अगली पीढ़ी के सुधारों पर मजबूत ध्यान बिन्दु के साथ यह बजट सभी क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण उन्नति के लिए मंच तैयार करता है।

–नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और 'अमृत काल' के सभी संकल्पों को सिद्ध करने है। आम बजट 2024-25 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव-दृष्टि है।

–योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी

बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'वरदान' है। यह एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वित्तीय योजना किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा देगी।

–शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

प्रॉपर्टी बेचने पर अब लगेगा झटका!, टैक्स तो घटा लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर मिलने वाला इंडैक्सेशन बेनिफिट खत्म

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और उससे जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। इनके तहत प्रॉपर्टी की बिक्री को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की परिभाषा में लाने के लिए 2 साल तक होल्ड करना ही काफी है। जबकि पहले ये समय सीमा 3 साल थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स की दर 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दी गई है। ये दोनों कदम तो लोगों को फायदा पहुंचाने वाले लग रहे हैं लेकिन इसके साथ ही सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर मिलने वाला इंडैक्सेशन बेनिफिट खत्म कर दिया है।

पुराने नियमों के तहत अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 10 साल पहले खरीदी थी और उसे अब बेचने जा रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओरिजनल खरीद मूल्य के आधार पर कैलकुलेट नहीं किया जाता। पुरानी लागत को 10 साल के इंफ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके नई लागत निकाली जाती है। इसके लिए सरकार की तरफ से कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्सेशन (सीआईआई) जारी किया जाता है। पुरानी लागत को सीआईआई के आधार पर एडजस्ट करने को ही इंडेक्सेशन बेनिफिट कहते हैं। इस इंफ्लेशन एडजस्टेट कॉस्ट को प्रॉपर्टी के बिक्री मूल्य से घटाने पर जो मुनाफा निकलता था, उस पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था।

बजट में घोषित नए नियम के तहत प्रॉपर्टी भले ही 10-15-20 या 25 साल पहले खरीदी गई हो, उसके उस वक्त के ओरिजिनल खरीद मूल्य को ही वास्तविक लागत मानकर कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। भले ही आपने प्रॉपर्टी को कितने भी लंबे समय तक होल्ड किया हो और उस दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी हों, लेकिन प्रॉपर्टी बेचते समय आपकी खरीद की लागत में इंफ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जाहिर है, इस नए नियम से पुरानी प्रॉपर्टी बेचने वालों पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ जाएगा।

इस मसले को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं

नए नियम से कैसे बढ़ेगी टैक्स देनदारी?

मान लीजिए आपने फरवरी 2013 में एक प्रॉपर्टी 55 लाख रुपए में खरीदी थी। अगर आप उस प्रॉपर्टी को अभी 1.35 करोड़ रुपए में बेचते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80 लाख रुपए होगा। लेकिन प्रॉपर्टी के खरीद मूल्य में इंडेक्सेशन बेनिफिट जोड़ने के बाद उसकी एडजस्टेड लागत 90.75 लाख रुपए आएगी। इस हिसाब से आपका कैपिटल गेन 44.25 लाख रुपए ही बैठेगा। इतने कैपिटल गेन पर पिछले रेट के हिसाब से आपको 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना था, जो करीब 8.85 लाख रुपए बैठता। लेकिन अब आपको इस पर कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरे 80 लाख रुपए पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। यानी एलटीसीजी टैक्स की 12.5 फीसदी की नई दर के हिसाब से आपको 80 लाख रुपए के दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर पूरे 10 लाख रुपए टैक्स के तौर पर भरने होंगे। यानी इस उदाहरण में आपको पूरे 1 लाख 15 हजार रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। यह सारा कैलकुलेशन हमने इंडेक्सेशन बेनिफिट के एक ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से किया है।

ऐसे होगा एलटीसीजी टैक्स का कैलकुलेशन

- फरवरी 2013 में खरीदी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कीमत : 55 लाख रुपए
- प्रॉपर्टी बेचने का साल : 2024-25
- प्रॉपर्टी का बिक्री मूल्य : 1.35 करोड़ रुपए

पुराने नियम के हिसाब से कैलकुलेशन

- इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद प्रॉपर्टी की इंफ्लेशन एडजस्टेड लागत : 90,75,000 रुपए
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन : 1,35,00,000-90,75,000 = 44,25,000 रुपए
- 44,25,000 के लाभ पर 20% की दर से एलटीसीजी टैक्स = 8.85 लाख रुपए

नए नियम के हिसाब से कैलकुलेशन

- इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना प्रॉपर्टी की लागत : 55 लाख रुपए
- इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना एलटीसीजी : 1.35 करोड़ रुपए-55 लाख रुपए = 80 लाख रुपए
- 80 लाख रुपए के लाभ पर 12.5% की दर से एलटीसीजी टैक्स : 10 लाख रुपए
- नए नियम की वजह से नुक्सान : 10 लाख-8.85 लाख = 1.15 लाख रुपए

Registration No.: MSCS/CR/803/2013

Regd. Office : 604 A, Pearls Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110 034
Ph. No. : 011-27355609
Email : info2021kisanagrotech@gmail.com
Website : www.kisanagrotech.in

Notice is hereby given that the Special General Meeting of the Members of M/s. Kisan Agro-tech Cooperative Society Limited will be held on Friday, the 2nd day of August, 2024 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Society situated at 604 A, Pearls Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110 034 to transact the following business :-

1. Appointment of Statutory Auditors of the Society.
2. Addition of New Members in the Society.

You are requested to make it Convenient to attend the Meeting.

For Kisan Agro-tech Cooperative Society Limited
(Sd/-) Pawan Kumar Kaushik
Vice Chairman

Date : 17.07.2024 Place : New Delhi

Note :
- A member is not entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself.
- Members are requested to immediately intimate any change in their registered address registered with the society.
- All the Statutory Registers can be inspected at the Registered Office of the society during the Business hours i.e. 09:30 to 05:30 PM.

Area of Operations : Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Rajasthan, Punjab and Himachal Pradesh.